दूसरा विषय यह है कि 98 प्वाइंट्स के ऊपर स्टेट और सेंटर के बीच आपस में बात होने के बाद इन 98 such points के ऊपर 13 जून, 2015 के अंदर स्टेट्स में कामकाज होना है। उस 98 प्वाइंट्स के ऊपर initiative भी लेना है। 98 प्वाइंट्स में से हर एक को 13 जून, 2015 को फिनिश करना है, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ को पहले भी कर सकते हैं और कुछ को बाद में भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक प्वाइंट के लिए टाइम लिमिट vary हो रही है। So, it is not that the States have not been given a guideline or the information has not been shared with them. During the meeting in December 28th when a national level meeting happened in Vigyan Bhawan, along with States, consultation was held, Mr. Chairman, Sir, and 98 such points on which initiatives will have to be taken at the State level have been shared with them; many of them are following and I am very happy to report that States are cooperating and all States are cooperating. We have just given a little example of what has happened. It does not mean that the other States are not doing. However, on the 98 points, initiatives have to be taken so that there is greater ease of doing business in the country. All States will have to complete on those 98 points by 30th June, 2015.

Strategy to achieve the production targets of SAIL

*62. SHRI DHIRAJ PRASAD SAHU : Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government has finalized a long term strategic plan for the Steel Authority of India Limited (SAIL) to achieve the production targets fixed by Government, if so, the details thereof;

(b) whether SAIL is having sufficient funds to achieve these targets;

(c) if so, the details thereof including the total funds utilized and their achievements, so far, in this regard; and

(d) if not, the manner in which the funds are likely to be mobilized for the expansion plan of SAIL and other public sector steel plants?

THE MINISTER OF STEEL (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) No, Sir. The Government does not finalize long term strategic plan for Steel Authority of India Limited (SAIL). However, SAIL has prepared a draft 'Vision 2025' envisaging hot metal production target of 50 million tonnes by the year 2025. The estimated investment for achieving this target would be about Rs.1,50,000 crore. The

investment proposals are yet to be firmed up. The source of funding will be through a combination of equity and debt. SAIL and other steel PSUs undertake their expansion and modernization programmes with a mix of their internal resources and market borrowings based on commercial considerations.

श्री धीरज प्रसाद साहूः सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा पहला पूरक प्रश्न यह है कि अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि "सेल" की कोई दीर्घकालिक कार्यनीति नहीं बनाई गई है, लेकिन क्या "सेल" ने अपने फेज्ड आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना पर तय लागत से अधिक खर्च कर दिया है? किन-किन कम्पनियों को तय लागत से अधिक पैसा चुकाना पड़ा है? विशेषकर, एल एंड टी कम्पनी को कितना अधिक पैसा चुकाया गया है? इस विलम्ब एवं नुकसान के लिए किन-किन कंपनियों तथा अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई हुई है? भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने "सेल" के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के संबंध में प्रश्न किया है। यह बात सच है कि जब पिछली बार यह निर्णय हुआ था कि "सेल" अपना आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण करे, तो यह उनका पहला अवसर था। इसलिए हमने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, टेंडर इत्यादि किए, लेकिन अनुभवहीनता के चलते बहुत सारे कांट्रैक्टर्स के असफल हो जाने के कारण इन प्रक्रियाओं में विलम्ब भी हुआ है और निश्चित रूप से कुछ राशि भी बढ़ी है। उस मामले में "सेल" के बोर्ड ने भी समीक्षा की है और उसका संज्ञान लिया है। सरकार ने भी समीक्षा के दौरान इस बात को संज्ञान में लिया है, आगे से इस बात की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का "सेल" ध्यान रखेगा।

श्री सभापतिः दूसरा प्रश्न।

श्री धीरज प्रसाद साहूः महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि मौजूदा विस्तार योजना एवं आधुनिकीकरण के मौजूदा फेज के उपरांत क्या "सेल" ने 23.46 मिलियन टन प्रति वर्ष के अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी प्लांटवार ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इसके अलावा, मौजूदा फेज के लिए "सेल" द्वारा लिए गए कर्ज का ब्योरा क्या है तथा ब्याज के रूप में प्रति वर्ष कितना रुपया चुकाना पड़ता है?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, "सेल" ने जब अपने आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण की योजना ली, तो उस पर लगभग 61 हजार करोड़ रुपया खर्च होना था और 10 हजार करोड़ रुपया माइंस को डेवलप करने के लिए खर्च होना था। "सेल" के राउरकेला स्टील प्लांट के विस्तारीकरण का कार्य पूरा हो गया है और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई है। बोकारो स्टील प्लांट का काम पूरा हो गया है और ट्रायल चल रहा है। बर्नपुर का काम पूरा हो गया है, उसका ट्रायल चल रहा है। दुर्गापुर और भिलाई का काम थोड़ा-सा शेष है जो सितम्बर तक पूरा हो जाएगा और जब यह काम पूरा होगा, तो निश्चित रूप से "सेल", जो आज 13 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता का उपक्रम है, वह 23 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता का उपक्रम हो जाएगा।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, modernization in the steel plant is a continuous process. This has been continuing since long. My point is that the capacity is increasing. But, at the same time, the hon. Minister must be knowing that it is not only SAIL but also all other steel producers in the country are facing a serious problem with regard to unrestricted import. It is practically dumping. The steel producers are facing lower NSR and that is going to impact their productivity which they are planning to increase by their continuous process of modernization. Incidentally, hon. Commerce Minister is also here. So, my question is: Whether you have brought to the notice of the Steel Ministry and SAIL that continuing import impacting steel sector. And, what concrete steps by the Government is taking to contain the continuing import which is targeted to be a zero duty import by 2016 as per an international arrangement treat between the regional countries.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I would like to know whether the Government is seriously planning on that or not. Otherwise, this continuous investment, ultimately, would turn unproductive and it would create a serious pressure on the entire economy. Is the Government seriously considering it? In their modernization programme, the Durgapur Steel Plant needs much more investment. It is only the partial modernization which has taken place, by which its full production capacity can't be harnessed. Would the hon. Minister consider augmenting the allocations and plan the modernization of the Durgapur Steel Plant, particularly?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, तपन सेन जी की जो चिंता है, निश्चित रूप से वह वाजिब है और जो इस समय स्टील का आयात बढ़ रहा है, उससे सभी लोग चिंतित हैं। इस समय हमारा लगभग 9 मिलियन टन आयात हो रहा है और 5 मिलियन टन का हम निर्यात कर रहे हैं। चूंकि इस्पात एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र में आता है और विश्व के अनेक देशों से जो करार हैं, वह भी इसमें एक कारण है। उधर चीन जैसे देशों में उनकी उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण वे हमारे बाजारों की ओर देख रहे हैं, लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है, सरकार ने उसे संज्ञान में लिया है और इस विषय में हम वित्त मंत्रालय से चर्चा में हैं। मुझे लगता है कि इस संकट से हम जल्दी उबरेंगे। जहां तक दुर्गापुर स्टील प्लांट का सवाल है, निश्चित रूप से प्रथम चरण में उसमें आंशिक इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है उसमें विस्तार से उसके आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम हाथ में लिया जाएगा।

SHRIMATI GUNDU SUDHARANI: Sir, the Thirteenth Schedule to Andhra Pradesh Reorganisation Act mandates that SAIL should establish an integrated steel plant in Khammam district in Telangana region. Sir, we have iron ore mines at Bayyaram in Khammam district. So, setting up of a steel plant there is very easy. I would like to know from the hon. Minister what SAIL has so far done to set up a steel plant in Khammam district of Telangana; whether any feasibility report has been prepared as mandated to be done in six months; if so, the details of the report. Thank you, Sir.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था, उस समय SAIL को एक मेंडेट दिया गया था कि वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों क्षेत्रों में स्टील प्लांट लगाए जाने की व्यावहारिकता का अध्ययन करे। SAIL ने वह अध्ययन किया, लेकिन उस मामले में जो संभावनाएं दिखनी चाहिए थीं, उनमें कमी दिखाई दे रही है। वहां से मुख्य मंत्री जी मिलने आए थे, तो हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट, सेल और हमारी स्टील मिनिस्ट्री से, तीनों के अधिकारियों की एक टीम बनाई है, जो दुबारा से उसका परीक्षण कर रही है। जब परीक्षण के निष्कष आएंगे, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, the reply says that there is a targeted production of 50 MT by the year 2025. I would like to know whether steps are being taken by the SAIL for enhancing the production capacity of the Salem Steel Plant and setting up of the captive thermal power plant for it.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, SAIL के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का जो काम चल रहा है, सभी प्लांटों का वह सितंबर में पूरा होगा, जिससे SAIL की जो उत्पादन क्षमता है, वह 13 मिलियन टन से बढ़कर 23 मिलियन टन हो जाएगी। वर्ष 2025 तक हम 50 मिलियन टन की क्षमता पूरी करें, ऐसा SAIL का दृष्टिकोण है और इस दृष्टि से वे दूसरे और तीसरे चरण में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, जिसमें सेलम भी शामिल है।

SHRI D. RAJA: Sir, the question was about the Salem Steel Plant.

MR. CHAIRMAN: I think, he has mentioned that. ..(Interruptions)..

श्री नरेन्द्र सिंह तोमरः सर, मैंने कहा कि सेलम उसमें शामिल है।

Damage to Rani- Ki -Vav due to running of trains

*63. SHRI DILIPBHAI PANDYA : Will the Minister of CULTURE be pleased to state:

(a) whether Government had in the past received any objection regarding damage to Rani-ki-Vav at Patan, Gujarat due to running of trains;

(b) whether Archaeology Department has taken any objection for new rail line passing nearby Rani-ki-Vav;

(c) whether to find out some solution, a joint meeting of Ministers/Officers of Railways and Archaeology Department have been held; and

(d) if so, whether Indian Railways is planning to lay the new railway line in such a manner that it would not damage world heritage Rani-ki-Vav?